इसके अतिरिक्त, जिला उद्योग, केन्द्रों में प्राप्त सभी आवेदनों की जांच वित्तीय जीव्यता, तकनीकी जीव्यता और अन्य यथा आवश्यक मानदण्डों के आधार पर की जाती है। इन मानदण्डों को पूरा करने वाले आवेदन बैंकों को आगे विचार करने हेतु भेजे जाते हैं।

1993-94 के दौरान ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जिन्हें प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण मंजूर किया गया है, के राज्यवार आंकड़े और वर्ष 1994-95 में 1-4-94 से 30-9-94 तक की अवधि में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत ऋण स्वीकृत किये गये शिक्षित बेरोजगार युवाओं के राज्यवार आंकड़े संलग्न अनुपत्र में दिये गये हैं। [देखिए परिशिष्ट 172 (अनुपत्र 64)]।

**विदेशी निवेश को प्रोत्साहन**

2643 **श्रीमति सुष्मा स्वराज :**
**श्री राम जेठमलानी :**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1991 से विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सुविधाओं की घोषणा की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उन घोषणाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जून, 1991 से सितम्बर, 1994 तक अनेक विदेशी संस्थानों ने भारत में निवेश करने की पेशकश की है,

(घ) यदि हां, तो अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, कनाडा, चीन, जापान और जर्मनी ने उक्तवित अवधि में निवेश हेतु कितने-कितने प्रस्ताव किये और सरकार ने उनमें से कितने-कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी है और

(ङ) सितम्बर, 1994 तक किस-किस देश के कुल कितने-कितने प्रस्तावों का निष्पादन हुआ है?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही)** : (क) और (ख) जी हां। 24 जुलाई, 1991 को संसद के दोनों सदनों को सभापटल पर रखे गए औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित मानदंडों के अधीन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (अर्थात औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुबंध-3 में सूचीबद्ध उद्योग) में 51% तक इक्विटी पूंजी वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वतः मंजूरी देता है। स्वतः अनुमोदन के लिए उपर्युक्त मानदंडों में न आने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्य प्रस्तावों पर सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अधीन विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) 1991 की नई औद्योगिक नीति ने विदेशी संस्थाओं सहित निवेशकों में पर्याप्त रूची पैदा की है। 1991 से अक्तूबर, 1994 के दौरान अमेरिका, फ्रांस, इंगलैंड रूस कनाडा, चीन, जापान और जर्मनी की कंपनियों/संस्थाओं से निवेश के लिए प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की देशवार संख्या विवरण I में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**।

(ङ) 1991 से अक्टूबर, 1994 की अवधि के दौरान इन देशों की कंपनियों/संस्थाओं से प्राप्त वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विवरण II में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**। तथापि, कार्यान्वित किए गए प्रस्तावों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

**विवरण-I**

| | 1991 से 1994 (अक्तूबर तक) के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों की कुल संख्या |
|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 507 |
| फ्रांस | 77 |
| इंगलैंड | 275 |
| रूस | 47 |
| कनाडा | 29 |
| चीन | 14 |
| जापान | 59 |
| जर्मनी | 267 |

विवरण-II

(रुपये करोड़ में)

| | 1991 से 1994 (अक्तूबर तक) तक वास्तव में प्राप्त राशि |
|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका | 848.58 |
| फ्रांस | 97 31 |
| इंग्लैंड | 534.37 |
| रूस | – |
| कनाडा | 1.74 |
| चीन | 0 14 |
| जापान | 383.66 |
| जर्मनी | 264.49 |

**Crisis in small, tiny and medium industries**

2644. SHRI JOYANTA ROY :
SHRI DEBABRATA BISWAS :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that small, tiny and medium industries are facing crisis presently due to unequal competition from the large houses and MNCs under the New Economic policy; and

(b) if so, what steps Government propose to take for the protection of the interests of this sector ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

**Approval for more foreign bids**

2645. SHRI RAMDAS AGARWAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to tate :

(a) whether Government have approved 56 more proposals envisaging a total "Rs. 600 crore foreign bids" as reported in the Hindustan Times' dated 2nd December, 1994;

(b) if so, how many proposals were considered during the year 1994 till date in comparison to 1993 and what is the number thereof cleared year-wise relating to foreign direct-investment in India;

(c) how many of the approved units have projected or are likely to project export earnings from Rs. 2,000 to 3,500 crores over a period of five years or so indicating location in each case in the country; and

(d) what is the number of units which are 100 per cent export-oriented and the sectors to which these belong and how many are in joint ventures, during the period 1994-95, State-wise ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) Yes, Sir.

(b) During 1994 (up to October), 865 proposals for foreign direct investment have been considered and approved as against 610 proposals considered and approval during the corresponding period in 1993.

(c) Many of the approved projects have export potential depending on the nature and type of items to be manufactured by these units. However, centralised data on projected export earnings of these units are not maintained.

(d) During the year 1994-95 (April to October), 332 proposals have been approved for setting up 100% export oriented units, in sectors, such as Food Processing, Granite, Leather shoes, Textile, Vegetable Oil and Vanaspati, Electronics, Studded Gold Jewellery and Computer Software. Of these, 116 proposals have been approved for setting up joint ventures with foreign investment. State-wise break-up of 100% export oriented units approved for setting up joint ventures with foreign investment is given in the statement.